आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 31 लखनऊ, शनिवार 21 नवम्बर 2026 सा 27 नवम्बर 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा- कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी, क्या बदले में नौकरियां और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चौम्बर ऑफ कॉमर्स यानी फिक्की की सालाना आमसभा में देश के उद्योगपतियों और कारोबारियों को आईना दिखाया। उन्होंने टैक्स सुधारों का जिक्र किया। आयकर में १२ लाख तक की छूट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी लेकिन क्या कारोबारियों ने नौकरियां बढ़ाईं? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कारोबारियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में सुधार किया? गौरतलब है कि २०१४ में सरकार में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कॉरपोरेट टैक्स में छूट दे रही है। लेकिन उस अनुपात में भारत में कॉरपोरेट सेक्टर नौकरियों के अवसर नहीं बढ़ा रहा है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में राहुल गांधी की अमेरिका में कही गई बातों का भी जवाब दिया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि किसानों और कारोबारियों को गाली देने से देश आगे नहीं बढ़ता।

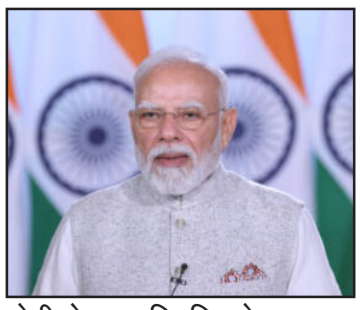

मोदी ने कहा कि पिछले १२ साल में भारत की इकोनॉमी बदली है और ५० करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बुधवार को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने कहा था कि इसके पीछे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी खामियां हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों को नसीहत देते हुए कहा कि कुछ कंपनियां विदेशों के लिए बेहतर और भारत के लिए कम गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती हैं। इस सोच को बदलना होगा। भारतीय ग्राहक भी अच्छी गुणवत्ता वाले सामान के हकदार हैं। प्रधानमंत्री ने कारोबारियों से घरेलू बाजार तक सीमित न रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को दूसरे देशों की जरूरतों और ग्राहकों की पसंद समझकर उत्पाद तैयार करने चाहिए। मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस के जरिए लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने कारोबारियों से बिना झिझक अपनी समस्याएं और सुधारों से जुड़े सुझाव देने को कहा। सरकार उनके साथ खड़ी है।

चक्रवात अकवान आज टकराएगा

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान अकवान का असर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में दिखने लगा। तूफान शुक्रवार को दोपहर तक समुद्र तट से टकराएगा। लेकिन उससे पहले ही कई राज्यों में तेज हवाएं चलने लगी हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश और तेज हवाओं के चलते भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और कोलकाता आने और जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तूफान के समुद्र तट से टकराने से पहले ओडिशा में ८० हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इसके खतरे को देखते हुए छह जिलों में १६ से २१ नवंबर तक स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राहत की करीब ७५ टीमें तैनात की गई हैं। तूफान के चलते कई जगह उड़ानें प्रभावित हुई हैं। विमानन कंपनियों ने यात्रियों को हवाईअड्डा जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान अकवान शुक्रवार दोपहर आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकरा सकता है। पहले कहा जा रहा था कि यह आंध्र प्रदेश में



समुद्र तट से टकराएगा। लेकिन अब इसने रास्ता बदल लिया है और आंध्र व ओडिशा के बीच टकराएगा। इस दौरान ६० से ११० किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। तूफान के असर से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश जारी है। नौसेना और दूसरी एजेंसियां बचाव की तैयारियों में जुटी हैं। चक्रवात के चलते १० राज्यों में मौसम बदलेगा।

नशे के सौदागरों पर योगी सरकार का निर्णायक प्रहार, बोले- अब तबाह होंगे नशे के कारोबारी

लखनऊ/गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया और संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई के बाद अब प्रदेश सरकार नशे के सौदागरों को तबाह करेगी। इसके लिए निर्णायक अभियान शुरू होगा। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा शिक्षा, कौशल व रोजगार पर लगाने का आह्वान किया। सपा के जुलूस के मसूम की हत्या का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि चुनाव के समय बिलों से निकलकर अराजकता फैलाने वाले सपा के गुंडों को कुचल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के दूसरे चरण के तहत आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के ५० हजार से अधिक छात्र–छात्राओं व प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरण की शुरुआत की। २३ विद्यार्थियों को उन्होंने स्वयं टैबलेट दिए। मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले गोरखपुर में सपा के जुलूस के दौरान दसवीं के छात्र की मौत का जिक्र करते हुए घटना को प्रदेश की पहचान पर काला धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने जा रहा छात्र चौरी–चौरा के क्रांतिकारी पूजन सिंह का प्रपौत्र था। योगी ने कहा कि चुनाव के समय बिलों से निकलकर



अराजकता फैलाने वाले तत्वों को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल स्किलिंग एंड एंप्लयमेंट जोन बनाया जाएगा। यहां जापानी और जर्मन भाषा समेत विभिन्न कौशल का प्रशिक्षण देकर युवाओं को देश–विदेश की कंपनियों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। ८ हजार लेखपाल, ३२ हजार पुलिसकर्मी और ४२ हजार से अधिक होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब २६ जनवरी तक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में 'मुन्ना भाई' और 'सैफई सिंडिकेट' का बोलबाला था, लेकिन अब टैलेंट के आधार पर तेजी से नियुक्तियां हो रही हैं। योगी ने कहा कि युवा फीड नहीं, फ्यूचर स्क्रॉल करें। रील देखने में ३० सेकंड लगाने के बजाय स्किलिंग पर तीन घंटे दें। सोशल मीडिया पर मिलने वाली सूचनाओं का फैक्ट चेक करने और डिजिटल सुरक्षा का भी ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में ६० लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए गए, जबकि दूसरे चरण में २५ लाख टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से जनगणना– २०२७ की स्वगणना और मतदाता सूची पुनरीक्षण में भी डिजिटल माध्यम से भागीदारी की अपील की।

आशियाना पुलिस के हत्थे चढ़े तीन नाबालिग वाहन चोर, चोरी की स्कूटी समेत १० बाइक बरामद

लखनऊ। आशियाना पुलिस ने गुरुवार देर शाम मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र स्थित देवीखेड़ा से ईको गार्डेन की तरफ जाने वाली रोड से से तीन नाबालिग चोरों की गिरफ्तार कर उनकी संख्या यूपी ३२ एल के ४६६२ बरामद किया गया है। देवी खेड़ा रोड के पीछे झाडिघ्योंमें छिपाकर रखी गई थी। जिसका मुकदमा स्थानीय थाने में दर्ज है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए चोरों में एक



निशानदेही पर चोरी की एक स्कूटी सहित दस बाइक बरामद कर थाने में दर्ज मुकदमे के तहत कार्रवाई कर बाल संरक्षण गृह भेज दिया है। आशियाना थाना प्रभारी गजेन्द्र राय ने बताया पकड़े गए १६ , १४ और १६ वर्ष के चोरों की निशानदेही पर थाना क्षेत्र स्थित एनीटाइम फिटनेस जिम, नियर प्रियम प्लाजा, रतन खंड, आशियाना लखनऊ से बीते ११ नवंबर को चोरी गई बाइक किशोर शातिर किस्म का चोर है, जो पूर्व में स्थानीय आशियाना थाने से चोरी के मुकदमे में बाल संरक्षण गृह जा चुका है। बरामदगी के आधार पर पकड़े गए तीनों नाबालिग शातिरों को थाने में दर्ज चोरी के मुकदमे के तहत कार्रवाई कर बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। बरामद किए वाहनों में एक स्कूटी सहित चोरी की दस बाइके शामिल हैं।

सम्पादकीय

लोकलुभावन योजनाओं की कीमत पर दांव पर लग रहा राज्यों का भविष्य

चुनावी लाभ के लिए नकद बांटने की बढ़ती होड़ से विकास कार्यों पर संकट, राजकोषीय अनुशासन और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन जरूरी देश की राजनीति में चुनाव जीतने के लिए लोकलुभावन घोषणाओं और मुफ्त सुविधाओं का चलन लगातार बढ़ रहा है। अब यह प्रवृत्ति केवल राजनीतिक वादों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि राज्य सरकारों के बजट का बड़ा हिस्सा भी इसकी भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। यह स्थिति केवल आर्थिक चिंता का विषय नहीं है, बल्कि देश के दीर्घकालिक विकास और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। इस पर अब गंभीर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की ताजा स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंसेज रिपोर्ट ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष २०२७ में विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले सात राज्यों ने वित्त वर्ष २०२६–२७ के बजट में बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजनाओं के लिए ३५ हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। यदि देश के सभी राज्यों को शामिल किया जाए तो ऐसी योजनाओं पर प्रस्तावित खर्च करीब चार लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि चुनावी राजनीति में सीधे नकद लाभ बांटने की योजनाएं किस तरह प्रमुख स्थान हासिल कर चुकी हैं। चिंता इसलिए भी गंभीर है कि वर्ष २०२२–२३ में इन योजनाओं पर राज्यों का कुल खर्च लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये था, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब ०.६ प्रतिशत था। वर्ष २०२६–२७ तक इसके बढ़कर जीडीपी के लगभग एक प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सब्सिडी पर होने वाला खर्च भी राज्यों के खजाने पर भारी पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष २०२४–२५ में २६ राज्यों ने सब्सिडी पर ४.४ लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जो उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग ११ प्रतिशत था। सवाल यह है कि जब राज्य सरकारों की आय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक खर्च और सब्सिडी में जा रहा है, तब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन कहां से आएंगे? विकास का अर्थ केवल तत्काल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्थाएं तैयार करना है, जो नागरिकों को भविष्य में आत्मनिर्भर बना सकें। यदि बजट का बड़ा हिस्सा राजस्व खर्च में ही समाप्त हो जाएगा तो पूंजीगत निवेश प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसका सीधा असर रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। हालांकि, यह भी समझना होगा कि हर नकद सहायता या सब्सिडी को अनावश्यक खर्च मान लेना उचित नहीं है। गरीब परिवारों, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कई परिस्थितियों में प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता जरूरतमंदों को राहत देने का प्रभावी माध्यम भी बनती है। लेकिन ऐसी योजनाओं का औचित्य उनकी जरूरत, लक्ष्य, वित्तीय क्षमता और वास्तविक सामाजिक लाभ के आधार पर तय होना चाहिए, न कि केवल चुनावी लाभ की संभावना से। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस प्रवृत्ति में राजनीतिक दलों के बीच कोई स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं देता। पीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार, २०२७ में चुनाव वाले सात राज्यों में पांच में भाजपा, एक में कांग्रेस और एक में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अलग–अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद नकद हस्तांतरण योजनाओं को लेकर सभी दलों का रुझान लगभग समान नजर आता है। इससे स्पष्ट है कि यह समस्या किसी एक दल तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी चुनावी राजनीति की व्यापक चुनौती बन चुकी है। अब समय आ गया है कि चुनावी घोषणाओं के साथ उनकी वित्तीय जवाबदेही भी अनिवार्य की जाए। प्रत्येक सरकार को यह बताना चाहिए कि किसी नई योजना पर कितना खर्च होगा, उसके लिए संसाधन कहां से आएंगे और उसका दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा। स्वतंत्र वित्तीय आकलन, पारदर्शिता और योजनाओं के सामाजिक परिणामों की नियमित समीक्षा भी जरूरी है। लोकतंत्र में जनकल्याण सर्वोपरि है, लेकिन जनकल्याण और चुनावी प्रलोभन के बीच अंतर समझना भी उतना ही आवश्यक है। सरकारों का दायित्व केवल वर्तमान मतदाता को आर्थिक लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है। यदि आज की राजनीतिक लोकप्रियता की कीमत कल का विकास चुकाएगा, तो इसका नुकसान अंततः आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए राज्यों को मुफ्त सुविधाओं और विकास निवेश के बीच संतुलन बनाना होगा। आखिरकार, किसी भी सरकार की सफलता का वास्तविक पैमाना चुनावी घोषणाओं की संख्या नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में आया स्थायी और सकारात्मक बदलाव होना चाहिए।

गोरखपुर में अखिलेश का हुंकार, बोले- इस बार भाजपा को नौ बटे निल करेगी जनता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचकर हवाई अड्डे से चौरी–चौरा के देवकही गांव तक 'पीडीए रथ' पर सवार होकर रोड शो किया। सपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, करीब २० किलोमीटर लंबे इस रोड शो का मकसद पूर्वांचल, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह नगर में राजनीतिक संदेश देना है। बाद में यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि गोरखपुर में उनके रोडशो में उमड़ी भीड़ यह दिखाती है कि भाजपा अपने गढ़ में कमजोर हो रही है। यादव के रोड शो में गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता सपा के झंडे लेकर रथ के साथ चलते रहे और पार्टी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। देवकही गांव पहुंचने पर यादव स्वतंत्रता सेनानी और शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके बाद वह भाजपा के पूर्व नेता विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह की १०वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस दौरे के दौरान बिन्नू सिंह के भाई अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि टप्पू आगामी विधानसभा चुनाव में चौरी–चौरा सीट से सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि, पार्टी ने अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बस रूपी 'पीडीए रथ' पर निकले इस रोडशो में भारी उत्साह देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी के साथ–साथ दौड़ रहे थे, पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और पोस्टर लिए हुए थे जिन पर लिखा था– 'टीपू इज बैक' और 'जेन जेड फेवरेट'। इस दौरान चुनाव प्रचार से संबंधित गीत बज रहे थे, जिनमें 'यूपी के कोने–कोने में भैयाजी को जिताना है' और '२०२७ में अखिलेश आ रहे हैं' जैसे गाने शामिल थे। कूड़ाघाट क्र सिंग के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने दो क्रेनों की मदद से एक विशाल माला पहनाकर यादव का स्वागत किया। रोडशो के दौरान, उन्होंने बस का दरवाजा खोलकर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। यादव दोपहर १२:३० बजे एक विशेष विमान से गोरखपुर हवाई अड्डे पहुंचे, जहां ढोल–नगाड़ों के बीच १,००० से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर छह युवा पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार भी किया। मध्यप्रदेश के मऊगंज से आए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राम सुख निषाद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है और यादव को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। भदोही से आए समाजवादी पार्टी के दो फुट लंबे कार्यकर्ता चांद बाबू भी पार्टी प्रमुख का स्वागत करने हवाई अड्डे पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बाद में यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि गोरखपुर में उनके रोडशो में उमड़ी भीड़ यह दिखाती है कि भाजपा का गढ़ गड़बड़ा गया है। उन्होंने कहा,"गोरखपुर में हमारे रोडशो में उमड़े जनसैलाब को देखकर जनता कह रही है कि 'किसी का गढ़ गड़बड़ा गया है!' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा,"इस बार गोरखपुर में जनता भाजपा को 'नौ बटे निल' कर देगी। पूरे गोरखपुर मंडल में एकजुट 'पीडीए' का समाज प्रभुत्ववादियों को धूल चटा देगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की ये पुकार,अहंकार की होगी हार।



राम मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा, दिसंबर तक वित्तीय क्लोजरय २०२७ तक बनेगा २० गैलरी वाला संग्रहालय

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब निर्माण से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता की जांच और संबंधित कंपनियों के साथ वित्तीय हिसाब–किताब अंतिम रूप देने पर जोर है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को कहा कि लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) के जिम्मे अब निर्माण का कोई काम शेष नहीं है। दिसंबर २०२६ के अंत तक निर्माण कार्यों से जुड़े वित्तीय क्लोजर की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, राम मंदिर परिसर के निकट सरयू नदी के पास बनने वाला संग्रहालय दिसंबर २०२७ तक तैयार होने की उम्मीद है। नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के बाद बताया कि पिछली बैठक में मुख्य रूप से निर्माण की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा हुई। अलग–अलग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) और टीसीई को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि अब प्राथमिकता निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और संबंधित कंपनियों के बिलों का अंतिम निस्तारण करने की है। इसमें भुगतान के साथ गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर आवश्यक कटौती भी शामिल होगी। उन्होंने बताया कि परकोटे को छोड़कर निर्माण के तहत तैयार की गई सभी परिसंपत्तियां राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई हैं। अब इनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। निर्माण एजेंसियों की ओर से बैंक गारंटी जारी करने की मांग भी की जा रही है। परिसर में अभी ऑडिटोरियम, ट्रस्ट कार्यालय और संग्रहालय से जुड़े कार्यों पर काम चल रहा है। इसके अलावा गेट नंबर तीन पर लोहे का गेट लगाया जाना बाकी है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि सरयू नदी के पास प्रस्तावित संग्रहालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। इसमें २० गैलरियां विकसित की जाएंगी। प्रत्येक गैलरी में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री, वीडियो और प्रस्तुत की जाने वाली कहानियों को लेकर विस्तृत योजना बनाई जा रही है। इसके लिए अलग–अलग गैलरियों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अनुमान है कि संग्रहालय के निर्माण और उसे विकसित करने में करीब एक वर्ष का समय लगेगा। इसे दिसंबर २०२७ तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के सभी स्थलों के दर्शन की सुविधा उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए अब मंदिर परिसर के भीतर बने अन्य मंदिरों और विभिन्न स्थलों के दर्शन तथा भ्रमण की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। श्रद्धालु बिना किसी रुकावट के परिसर में उपलब्ध निर्माण और सुविधाओं को देख सकेंगे। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

योगी का विपक्ष पर हमला, बोले– हारने पर ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं को दोष देती है कांग्रेस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य में २०२७ के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा नेतृत्व अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के जरिये और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाएगा, क्योंकि पिछले साढ़े नौ वर्षों में राज्य की तस्वीर बदली है। उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या भाजपा २०२७ के विधानसभा चुनावों में ४०३ में से ३२० सीट हासिल करने के लक्ष्य को पार करेगी, तो उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगाय हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर कोई संख्यात्मक आश्वासन नहीं दिया। एक निजी चौनल के कार्यक्रम 'राइजिंग भारत समिट' में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ''किसी भी महिला, युवा, व्यापारी या गरीब से पूछिए, वे कहेंगे कि (भाजपा) सरकार को फिर से सत्ता में आना चाहिए। जिन्हें विकास पसंद नहीं है, जो हर पहल में नकारात्मकता देखते हैं और अव्यवस्था का माहौल चाहते हैं, वे निराश होंगे। कानून–व्यवस्था में सुधार को आर्थिक विकास से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगों और कर्फ्यू वाले माहौल में निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास एवं रोजगार पैदा करना असंभव है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले एक दशक में २.३० लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की है तथा ३२,००० और पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण क्षमता को एक बार में ६,००० से बढ़ाकर ६०,००० करने, सभी १८ मंडल मुख्यालयों में फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने, सभी ७५ जिलों में साइबर



पुलिस थाने खोलने और सात शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का भी जिक्र किया। आदित्यनाथ ने एसआईआर को मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसमें से मृत व्यक्तियों और गैर–नागरिकों के नाम हटाए जाने चाहिए, जबकि हर पात्र वयस्क भारतीय नागरिक का नाम इसमें शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने में योगदान देंगे कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के आरोपों और एसआईआर तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर सवाल उठाए जाने पर पलटवार करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अपनी चुनावी हार के लिए संवैधानिक संस्थाओं को दोष देती है। उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा, ''जब वे जीतते हैं तो यह उनकी जीत होती है, लेकिन जब वे हारते हैं तो ईवीएम गलत हो जाती है, एसआईआर गलत हो जाता है और निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया जाता है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता उन सभी अभियानों का हिस्सा बन जाते हैं, जो भारत के हितों के खिलाफ होते हैं या जो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। आदित्यनाथ ने कहा, ''दुर्भाग्य से, (राहुल में) अब भी परिपक्वता की कमी है। उन्हें ऐसे बेतुके मुद्दों से बचना चाहिए और योग्यता, तथ्यों तथा सबूतों के आधार पर बात करनी चाहिए। ब्राह्मणों मे भीतर असंतोष की चर्चाओं के बीच, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सामाजिक गठबंधन "पीडीए" में 'पंडितों' (ब्राह्मणों) के लिए एक और 'पी' जोड़ने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा के कुछ नेताओं के बयानों का हवाला दिया और कहा कि उनके बयानों एवं हिंदू समुदायों के प्रति पार्टी के पिछले रवैये से उनकी असल सोच का पता चलता है।

आजम खान की रिहाई से यूपी की सियासत में हलचल, सपा के लिए बढ़ेगी मुस्लिम राजनीति की ताकत

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तीन महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान की रिहाई सपा के लिए बड़ी राहत की बात है। खास कर असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता के कारण भी सपा को आजम खान की जरुरत महसूस हो रही थी। पिछले दिनों अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों ने जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की थी। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान की बुधवार को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहाई हुई। गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में बुधवार को उनकी जमानत से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई हुई। कोर्ट ने जमानत के लिए ५०–५० हजार रुपए के दो जमानती और ५० हजार रुपए के निजी मुचलके की शर्त रखी थी। इसके साथ ही अदालत के निर्देश के अनुसार एक हलफनामा भी दाखिल किया गया। आजम खान की रिहाई पर उनकी पत्नी तजीन फातमा ने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि उनको हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा रहा है। उन्होंने कहा, 'मुझे हमेशा अल्लाह पर बहुत भरोसा रहा कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। जब जुल्म का प्याला भर जाता है, तो अन्याय अपनी हद तक पहुंच जाता है। जिस तरह आजम साहब को जेल के गेट से ईडी ले गई, वह शायद जुल्म की आखिरी हद थी। मुझे भरोसा था कि न्याय मिलेगा'। उन्होंने रिहाई को सच और न्याय की जीत कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिलने के बाद



आजम खान जेल से बाहर निकलने वाले थे। लेकिन सुबह सात बजे ईडी ने जेल गेट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी उन्हें पूछताछ के लिए भी ले गई थी। आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को अदालत में चुनौती दी थी। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मंगलवार को उनको अंतरिम जमानत दे दी।

अखिलेश ने दोहराई जातीय जनगणना की मांग

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाति आधारित जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा है कि जातिगत जनगणना ही 'सामाजिक न्याय' का असली रास्ता है। इससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार और सम्मान मिल सकेगा। श्री यादव ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। जातीय जनगणना होगी तो सामाजिक न्याय का रास्ता खुलेगा। भाजपा सरकार ने लेटरल इंट्री से आरक्षण छीना।



पेपर लीक करा दिए। यह वह सरकार है जो सामाजिक न्याय के राज के रास्ते पर नहीं चलना चाहती है। लोगों की नौकरी रोजगार छीन रही है। उन्होने मांग नौकरियों में आरक्षण छीना। २६ हजार स्कूल बंद करा दिए और जितनी भी सरकारी नौकरियों थी जिन पर युवाओं का हक था, उसके नौकरियों में लूट के सवाल पर उन्होने कहा कि अगर लूट होती थी और दस साल के बाद भी लूट की बात कर रहे हैं तो इस सरकार पर भरोसा कौन करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होने कहा कि योगी वह होता है जो सच बोले। सच्चा संत वह होता है जो जनता को गुमराह न करे और साजिश न करे क्योंकि संत साजिश नहीं कर सकता। की कि सरकार जातीय जनगणना कराए और आबादी के हिसाब से सभी को उसका हक और सम्मान दिला दें। २०१७ से पहले सरकारी

दुकान खाली कराने को लेकर विवाद के बीच फोटोग्राफी शॉप से ढाई लाख का सामान चोरी, तीन लोगों पर शक जताया

लखनऊ। दुकान खाली कराने को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक फोटोग्राफी दुकानदार ने तीन लोगों पर उसकी दुकान से करीब ढाई लाख रुपये का सामान चोरी कराने का संदेह जताया है। पीड़ित का आरोप है कि दुकान खाली नहीं करने पर उसे पहले फोन पर धमकियां दी गई थीं। घटना के बाद पीड़ित ने माल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रोहित का आरोप है कि अंकुरेश्वर सिंह उर्फ अंकुर, मल्लिकार्जुन और सोनू सिंह उर्फ राणा उसकी दुकान खाली कराने का दबाव बना रहे थे। दुकान खाली करने से इनकार करने पर उसे फोन करके धमकाया गया था। आरोप है कि दुकान नहीं हटाने पर उसे तुड़वाने और सामान गायब कराने की धमकी भी दी गई थी। पीड़ित ने बताया कि धमकी से संबंधित फोन रिक र्डिंग भी उसके पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि दुकान से हुई चोरी की घटना के पीछे भी वही लोग हो सकते हैं, जो पहले से दुकान



खाली कराने का दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। माल थाना क्षेत्र के बदैयां गांव निवासी रोहित कश्यप ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी फोटोग्राफी की दुकान अक्षयवट हरिवंश बाबा मंदिर मंझी, निकरोजपुर में स्थित है। इसी दुकान से उसके परिवार की आजीविका चलती है। पीड़ित के मुताबिक, गुरुवार व शुक्रवार की रात अज्ञात चोर दुकान में घुसकर दो प्रिंटर, तीन पेनड्राइव, तीन मेमोरी कार्ड, एक बैटरी, एक यूपीएस, एक कैमरा समेत अन्य जरूरी सामान चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब दो लाख पचास हजार रुपये बताई गई है।

आर्थिक संकट के मुहाने पर है भारत

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह बात कही है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने लोकतंत्र खतरे में होने से लेकर मीडिया पर दबाव होने और वोट चोरी होने से लेकर अर्थव्यवस्था के भारी संकट में फंसने की बात कही। राहुल गांधी ने अमेरिकी युवाओं से बात करते हुए कहा कि भारत में युवाओं को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका के दो दिन के दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी खामियां हैं। राहुल ने कहा कि युवाओं में बढ़ती निराशा की मुख्य वजह यह है कि उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आता। राहुल ने दुनिया के और भी कई देशों की मिसाल दी, जहां आंदोलन हो रहे हैं और कहा कि जहां भी आर्थिक संकट है वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल बुधवार



को न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और फैकल्टी के सामने बोल रहे थे। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को सामान्य अभियान से बिल्कुल अलग बताया। उन्होंने कहा, 'इस अभियान में जितना पैसा खर्च किया गया, वह अनुमान से २०, ३०, ४० या ५० गुना तक ज्यादा था। इतना पैसा कहां से आया। इस अभियान में खर्च की गई रकम को लेकर कई सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना चाहिए'। राहुल ने कहा, 'युवाओं में मौजूदा हालात को लेकर निराशा है। इनमें एक वर्ग मध्यमवर्गीय परिवारों से आता है और उसने औपचारिक शिक्षा हासिल की है। हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आता'। राहुल के इस बयान पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर में कहा, 'राहुल विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करते हैं। वो भारत की इकोन मी को डिजास्टर बताते हैं, लेकिन भारत नहीं उनकी सोच डिजास्टर है'।

चुनाव बहिष्कार नहीं करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वोट चोरी और चुनाव चोरी के आरोपों के बावजूद उनकी पार्टी चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगी। यानी चुनाव लड़ती रहेगी। अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन शिकागो में एक बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। राहुल ने फिर यह दावा किया कि उनको चुनाव आयोग के अंदर से खबरें मिल रही हैं। असल में राहुल बार बार कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। इस पर उनसे पूछा गया था कि ऐसे में उनकी पार्टी चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करती है। इसका जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि चुनावों का बहिष्कार करने से लोकतंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देना चाहती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दोहराया कि २०२४ का लोकसभा चुनाव वैध नहीं था। उन्होंने कहा कि चुनाव में कई फर्जी मतदाता थे। एक ब्राजीलियाई महिला के नाम से विधानसभा चुनाव में २३ बार वोट डाले गए, जबकि वह कभी भारत आई ही नहीं। शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत में ही राहुल से यह भी बताया कि उनकी पार्टी या भारत का विपक्ष इतनी गड़बड़ी के बावजूद चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करता। अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस को राहुल को विदेश भेजने पर पैसा खर्च करने की बजाय उनका एआई मॉडल भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल बार बार एक ही बातें दोहराते हैं, एआई मॉडल उनसे बेहतर काम कर सकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी चुनावी गड़बड़ियों की बात कही थी और साथ ही यह भी कहा था भारत



की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है। बहरहाल, राहुल ने चुनाव बायकॉट की बात पर कहा, 'हम जान बूझकर चुनावी बहिष्कार का कदम नहीं उठा रहे हैं। चुनाव आयोग खुद अब अंदर से हमें जानकारी दे रहा है। इसलिए यह ढांचा कब ढहेगा, यह सिर्फ समय की बात है'। उन्होंने आगे कहा, 'चुनाव आयोग में वरिष्ठ लोग अब कह रहे हैं कि हम यह और नहीं कर सकते'। राहुल ने बातचीत के दौरान कहा, 'हम गैर लोकतांत्रिक भारत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। यह भारत के अधिकांश लोगों की भावना है'। उन्होंने विपक्ष के आंदोलन और प्रदर्शनों को लेकर कहा, 'विपक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों की बिना डर अपनी बात कहने की सबसे बड़ी ताकत फिर से बहाल हो। यह ताकत आगे भी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनी रहेगी। हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम यह लड़ाई जीत रहे हैं'।

तकनीकी व्यवधानों के बाद अमेरिकी साइबर निदेशक बर्खास्त

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय साइबर निदेशक सीन केयर्नक्र स को पद से हटा दिया है। देश भर में हवाई यात्रा, बैंकिंग सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों को बाधित करने वाले कई तकनीकी व्यवधानों के बीच प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर बढ़ती जांच के बाद यह कदम उठाया गया है। श्री केयर्नक्र स साइबर सुरक्षा नीति और रणनीति के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख सलाहकार थे। अमेरिका के कई मीडिया संस्थानों की खबरों के अनुसार, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी मजबूत विशेषज्ञता नहीं होने के कारण राष्ट्रपति ने उन्हें पद से हटाए जाने का समर्थन



किया था। पिछले सप्ताह आए तकनीकी व्यवधानों के दौर के बाद से राष्ट्रीय साइबर निदेशक को हटाया जाना ट्रंप प्रशासन का पहला बड़ा कार्मिक बदलाव है। इन व्यवधानों में माइक्रोस फ्ट की वैश्विक सेवा ठप होना शामिल है, जिससे करोड़ों उपयोगकर्ता प्रभावित हुए, साथ ही देश भर में हवाई यात्रा थमने से १८,००० से अधिक उड़ानें बाधित हुईं। सूत्रों के अनुसार, संघीय सरकार में साइबर सुरक्षा नीति और रणनीति की देखरेख करने वाले श्री केयर्नक्र स की जगह अस्थायी रूप से रक्षा विभाग की मुख्य सूचना अधिकारी कर्स्टन डेविस को नियुक्त किया जाएगा। गुरुवार रात जारी एक बयान में श्री केयर्नक्र स ने ट्रंप प्रशासन में अपने कार्यकाल को "जीवन भर का सम्मान" बताया।

पीएफ से निकाल सकेंगे ६० फीसदी पैसा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भविष्य निधि खाते यानी पीएफ से पैसे की निकासी को लेकर बड़ा फैसला किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने तय किया है कि अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से ज्यादा पैसा निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने ५५ साल से कम उम्र के कर्मचारियों के लिए नौकरी के दौरान पैसे निकालने की सीमा ७५ से बढ़ा कर ६० फीसदी कर दी है। इसके अलावा, ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव यह किया है कि पीएफ से पैसा निकालने के लिए एक साल तक नौकरी करने की शर्त हटा दी है। नए नियम के तहत अब पीएफ का सदस्य बनने के सिर्फ दो महीने बाद ही कोई कर्मचारी बेरोजगारी की स्थिति में पैसा निकाल पाएंगे। ईपीएफओ ने पैसे निकालने के अन्य नियम भी बहुत स्पष्ट कर दिए हैं। इसके मुताबिक खुद की या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी और अस्पताल का बिल भरने के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं। खुद की या बच्चों और परिवार के सदस्यों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने के लिए, खुद की या परिवार के किसी सदस्य की शादी के खर्चों के लिए और नया घर या फ्लैट खरीदने, जमीन खरीदने, मकान बनवाने, होम लोन चुकाने या पुराने घर की मरम्मत कराने के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में भी पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी।

प्रदूषण सर्टिफिकेट की वैधता में बदलाव

नई दिल्ली। बढ़ते वायु प्रदूषण से हो रही परेशानी के बीच केंद्र सरकार ने गाड़ियों के प्रदूषण सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में बदलाव करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी नए नियमों के तहत छह साल तक पुरानी बीएस छह मॉडल की निजी गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट अब तीन साल तक वैध रहेगा। वहीं, छह साल से ज्यादा और १० साल तक पुरानी निजी गाड़ियों को हर साल सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने १३ नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। गुरुवार को राजपत्र में प्रकाशित होते ही ये नियम लागू हो गए। नए नियमों में निजी और क मर्शियल वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की अलग अलग वैधता अवधि तय की गई है। ये बदलाव केंद्रीय मोटर वाहन कानून के तहत किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अगर मौजूदा सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त होने से १० दिन पहले के भीतर रिन्यूअल कराया जाता है, तो नया सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट के समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नए नियम लागू होने से पहले जारी किए गए सर्टिफिकेट पर बदली हुई वैधता अवधि पहली बार रिन्यू कराने के बाद लागू होगी।

ईरान रासायनिक और जैविक हथियार विकसित कर सकता है: ट्रंप

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी हमलों से अपने परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचने के बाद ईरान अब रासायनिक या जैविक हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने दावा किया कि ऐसे संकेत हैं कि परमाणु क्षमता हासिल करने की कोशिशों को अमेरिका द्वारा रोके जाने के बाद ईरान अब अपना ध्यान रासायनिक और जैविक हथियारों की ओर केंद्रित कर रहा है। श्री ट्रंप ने फ क्स न्यूज के एक रिपोर्टर से कहा वे गैसों और जैविक हथियारों पर विचार कर रहे हैं क्योंकि हमने परमाणु हथियारों के मामले में उनके रास्ते बंद कर दिये हैं। श्री ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान को उसके परमाणु इरादों को पूरा करने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा हमने उनके रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने ईरान की भविष्य की गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा देखते हैं पहली जनवरी के बाद क्या होता है। उन्होंने इसके साथ ही ईरानियों को 'बहुत बुरे लोग' के रूप में संबोधित किया। उनके ये बयान तब आये हैं जब अमेरिकी मीडिया, विशेष रूप से सीएनएन ने अमेरिकी खुफिया आकलन का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि ईरान वाशिंगटन डीसी में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को रासायनिक हथियारों से निशाना बनाने की योजना बना रहा हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान द्वारा संभावित हमले की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि देश को फिलहाल किसी तत्काल खतरे का सामना नहीं करना पड़ रहा है। गृह सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन ने भी कहा कि किसी हमले के होने का कोई संकेत नहीं है। श्री ट्रंप ने हालांकि अमेरिकी ध रती पर हमले की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वाशिंगटन के लोगों को चिंतित होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई हमला होने वाला है लेकिन चेतावनी दी कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो इसका बहुत कड़ा जवाब दिया जायेगा। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है, तो हम उनका नामोनिशान मिटा देंगे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने श्री ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने वाशिंगटन पर आरोप लगाया कि वह 'बड़े



पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों' के बारे में झूठे दावे करने की अपनी पुरानी आदत दोहरा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने इन आरोपों की तुलना २००३ में इराक पर हमले से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के प्रशासन द्वारा किए गए दावों से की है। उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने इराक के 'जनसंहार के हथियारों' के कार्यक्रम के सबूत पेश करने का दावा किया था। श्री बकाई ने सोशल मीडिया पर कहा ईरानी परमाणु खतरे के बड़े विचार के बाद अब अमेरिकी अधि ाकारी दावा कर रहे हैं कि ऐसे संकेत हैं कि ईरान जैविक या रासायनिक हथियार विकसित कर रहा है!" उन्होंने कहा आरोप तो बदलते रहते हैं लेकिन इनके पीछे का विचार वही पुराना और जाना–पहचाना है। ऐसा लगता है कि दुनिया से एक बार फिर यह उम्मीद की जा रही है कि वह सब कुछ भूल जाए। यह सवाल उठाते हुए कि क्या अमेरिकी अधि ाकारी यह उम्मीद करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इराक युद्ध को भूल जायेगा, श्री बकाई ने २००३ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने श्री कॉलिन पॉवेल की प्रस्तुति को याद किया। उन्होंने कहा क्या अमेरिकी अधि ाकारियों को सच में लगता है कि दुनिया २००३ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने कॉलिन पॉवेल की उस कुख्यात घटना को भूल जायेगी, जब उन्होंने इराक के जनसंहार के हथियारों से जुड़े खतरे को दिखाने के लिए एक छोटी शीशी हवा में लहराई थी?" श्री बकाई ने कहा वह पल आध ुनिक इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं और राजनीतिक धोखों में से एक का स्थायी प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि ये नये आरोप भी उसी 'धोखे वाली पटकथा' का हिस्सा लगते हैं। इससे पहले ईरान ने गुरुवार को दावा किया कि इस जलडमरूमध्य में दो और तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंगों से टकरा गये, जिससे उनमें आग लग गयी। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी ने हालांकि पुष्टि की कि उनके एक जहाज पर किसी वस्तु के टकराने के बाद चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया है। बहरीन और कुवैत ने भी कहा कि उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की ओर से दागे गये हथियारों को बीच में ही रोक दिया।

भारतीय कंपनियों ने रोकी सऊदी की उड़ानें

नई दिल्ली। भारतीय विमानन कंपनियों ने सऊदी अरब की उड़ानों में बड़ी कटौती की है। यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से हो रहे हमले के कारण सऊदी अरब में खतरा बढ़ रहा है और इसे देखते हुए एयर इंडिया, इंडिगो और आकासा एयर ने अपनी उड़ानों में कटौती की है। इंडिगो ने तो ३० नवंबर तक देश के चार प्रमुख शहरों के लिए अपनी सभी उड़ानें रद कर दी हैं। इंडिगो ने जेद्दा, मदीना, रियाद और दम्माम से आने जाने वाली सभी उड़ानों का संचालन फिलहाल स्थगित कर दिया है। विमानन कंपनी ने बताया कि उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को बुकिंग के दौरान दिए गए संपर्क विवरण जरिए इसकी जानकारी दी जा रही है। कंपनी ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि वह क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों का आकलन कर रही है। यात्रियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उसने यह भी कहा कि उसके लिए यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि सऊदी अरब में हाल के दिनों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं। देश के विभिन्न शहरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमलों की धमकियों के बाद क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तभी विमानन कंपनियों ने उड़ानों के संचालन की समीक्षा की हैं। कई कंपनियों ने अपनी सेवाओं को स्थगित करने या उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव करने का फैसला किया है। इंडिगो के अलावा अन्य भारतीय विमानन कंपनियोंने भी सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों में बदलाव किया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद और दम्माम के लिए अपनी सेवाएं ३० नवंबर तक स्थगित कर दी हैं। वहीं, जेद्दा के लिए उनकी उड़ानें अलग अलग समयसीमा के तहत प्रभावित हैं। इसी तरह अकासा एयर ने भी जेद्दा और रियाद के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन नवंबर के अंत तक बढ़ा दिया है।

आसियान–भारत के संबंध मजबूत होंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिपींस की राजधानी मनीला में हुए आसियान–इंडिया समिट में कहा कि भारत का विकास और आसियान देशों की समृद्धि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि भारत विकास करेगा तो उससे आसियान देशों को भी फायदा होगा और साथ ही आसियान की समृद्धि भारत के विकास को गति देगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मुफ्त ई वीजा सुविधा शुरू करने से लेकर समुद्र के रास्ते कारोबार सहित कई प्रस्ताव रखे। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि विकसित भारत २०४७ और आसियान का २०४५ का विजन दोनों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने २३वें आसियान–इंडिया शिखर सम्मेलन में दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव रखे। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पर्यटन, समुद्री सुरक्षा, तकनीक, ऊर्जा, शिक्षा और युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने की पहल का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने रखा। बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने आसियान



देशों के पर्यटकों को भारत आने के लिए मुफ्त ई वीजा देने का प्रस्ताव रखा है। मोदी ने समुद्र के रास्ते व्यापार और आवाजाही बढ़ाने, समुद्र से जुड़ी रिसर्च, प्रोंतिक आपदाओं से निपटने, तटरक्षक बलों के बीच तालमेल और समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर लंबे समय तक काम करने की योजना भी आसियान देशों के सामने रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर अपराध ों की जांच और डिजिटल सबूत जुटाने के लिए साझा साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तकनीक और जानकारी साझा करने के लिए तकनीकी आदान प्रदान का प्रस्ताव भी रखा। खनिज के क्षेत्र में खास कर रेयर अर्थ मैटेरियल्स की खोज और खनन के क्षेत्र में मिल कर काम करने का प्रस्ताव भी प्रध ाानमंत्री ने रखा। उन्होंने युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के उपाय करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष तकनीक और उससे जुड़ी नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए भी आसियान और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आसियान देशों के ज्यादा छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा मोदी ने २०२७ में होने वाले वर्ल्ड अ डियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में आसियान और भारत की क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन बनाने का प्रस्ताव भी अपने भाषण में दिया।

कांग्रेस, सीजेपी, आप, आइसा को नोटिस

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हुए प्रदर्शनों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा को नोटिस जारी किया है। दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। इस याचिका में गया है कहा कि जंतर मंतर और रामलीला मैदान में प्रदर्शनों से व्यापारियों के कारोबार को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास कई बड़े थोक बाजार



हैं, इसलिए यहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर रद्द करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नवंबर को रामलीला मैदान में रैली की थी। उससे पहले कांग्रेस ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था। दूसरी ओर सीजेपी, आप और आइसा ने १० अक्टूबर को जंतर मंतर पर और १६ अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रदर्शन किया था। सीजेपी के जंतर मंतर प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने ४५ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। व्यापारियों ने राहुल दिवाली की खरीदारी के हवाले राहुल गांध ी से भी रैली स्थगित करने की मांग की थी। उस समय भी व्यापारी कोर्ट में पहुंचे थे।

यूपी चुनाव २०२७: सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की कवायद तेज, योगी समेत चार दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव २०२७ से पहले भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस अहम जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के चार वरिष्ठ नेताओं को लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर उनकी सीटों की मांग और अपेक्षाओं का आकलन करेंगे। इसी सप्ताह बातचीत शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय लोकदल (रालोद), उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को अपना दल एस, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को निषाद पार्टी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तय जिम्मेदारी के तहत ये नेता सहयोगी दलों से उनकी अपेक्षित सीटों और उन पर दावे के आधार को समझेंगे। इसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। रिपोर्ट के आधार पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सहयोगी दलों के साथ आगे की बातचीत करेगा और सीट बंटवारे का अंतिम फार्मूला तय किया जाएगा। भाजपा के लिए इस बार सीटों का बंटवारा आसान नहीं रहने वाला है। पिछले चुनाव की तुलना में सहयोगी दलों की संख्या दो से बढ़कर चार



हो गई है। ऐसे में सभी दलों की मांगों और चुनावी समीकरणों के बीच संतुलन बनाना पार्टी के लिए चुनौती होगा। रालोद और सुभासपा पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थीं। रालोद ने ३३ और सुभासपा ने १८ सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। दोनों दल इस बार भी लगभग इसी स्तर की हिस्सेदारी चाहते हैं। हालांकि, भाजपा की योजना रालोद को अधिकतम १८ और सुभासपा को १० सीटें देने की है। ऐसे में दोनों नए सहयोगियों के साथ सीटों को लेकर मोलभाव आसान नहीं दिख रहा। भाजपा के पुराने सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी भी इस बार सीटों को लेकर अपनी मांग रख सकते हैं। अपना दल एस ने वर्ष २०१७ के विधानसभा चुनाव में ११ में से नौ और २०२२ में १७ में से १२ सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में पार्टी इस बार भी अधिक सीटों की अपेक्षा रख सकती है। वहीं, निषाद पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में १४ सीटें मिली थीं, लेकिन इनमें से छह सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। ऐसे में निषाद पार्टी भी अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने का दबाव बना सकती है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती रालोद और सुभासपा की मांगों को लेकर होगी। दोनों दल पिछली बार सपा गठबंधन में जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी उसी स्तर की हिस्सेदारी चाहते हैं। दूसरी ओर भाजपा दोनों को इससे कम सीटें देने की तैयारी में है। ऐसे में सहयोगियों के साथ बातचीत का रुख और केंद्रीय नेतृत्व का अंतिम फैसला यूपी चुनाव के गठबंधन समीकरणों की दिशा तय कर सकता है।

मां सावित्री देवी के अंतिम दर्शन के लिए उत्तराखंड रवाना हुए सीएम योगी, पीएम मोदी ने फोन कर जताया शोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी के अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। ६१ वर्ष की उम्र में उनकी मां का निधन शुक्रवार को हो गया। मां के निधन की खबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने फोन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और उनकी माता के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी और उनके परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कीं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांस ली। पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी सर्वेश पंवार ने उनके निधन की पुष्टि की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी की सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनके पार्थिव शरीर को पैतृक आवास पर रखा गया है। शनिवार को हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार



होने की संभावना है। एसएसपी सर्वेश पंवार के अनुसार, पुलिस और जिला प्रशासन सीएम योगी के परिवार के संपर्क में हैं। अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी की मां के निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक जगत की कई हस्तियों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री के प्रति संवेदना जताते हुए लोगों ने दिवंगत सावित्री देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी के हजारों कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी सेवा अवधि की पेंशन, २०२१ और २०२५ के कानून रद्द

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्चतम न्यायालय ने उन दो कानूनों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत कार्य आधारित, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और श्मस्टर–रोलश कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन के लिए जरूरी श्अर्हक सेवाश की गणना में शामिल नहीं किया जाता था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, २०२१ तथा उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, २०२५ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने १८ नवंबर को सुनाए गए ८६ पन्नों के फैसले में कहा कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं शुरुआत में कार्य आधारित, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी या 'मस्टर रोल' के आधार पर ली गई थीं, लेकिन बाद में किसी विधिवत बनाई गई योजना के तहत उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं, उन्हें केवल शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा, ''यह स्पष्ट है कि विधिवत बनाई गई योजना के तहत नियमितीकरण होने के बाद कर्मचारी नियमित प्रतिष्ठान का हिस्सा बन जाता है और उसकी सेवा नियमित सेवा में शामिल हो जाती है। इसके साथ ही उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रेकृति का महत्व समाप्त हो जाता है।'' फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, ''नियमितीकरण के बाद, ऐसी नियुक्ति का शुरुआती स्वरूप कानूनी रूप से अप्रासंगिक हो जाता है। इसलिए, बाद में इसे इस आधार के रूप में फिर से नहीं उठाया जा सकता कि कर्मचारी को नियमित सेवा का हिस्सा होने के नाते मिलने वाले सेवा और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से वंचित किया जाए या उन्हें कम किया जाए। ''शीर्ष अदालत ने कहा,'' नतीजतन, संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति के शुरुआती स्रोत या स्वरूप का इस्तेमाल उन्हें उन सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता, जो एक नियमित कर्मचारी के तौर पर उन्हें मिलने चाहिए।'' फैसले में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दोनों कानूनों को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया है। इस फैसले से लोक निर्माण, सिंचाई और भूजल समेत राज्य के विभिन्न विभागों के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। इन कर्मचारियों ने नियमित होने से पहले कई वर्षों तक सेवा दी थी, लेकिन पेंशन तय करते समय उनकी शुरुआती सेवा अवधि को शामिल नहीं किया गया था। पीठ ने २०१६ के अपने महत्वपूर्ण फैसले 'प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' को दोहराते हुए कहा कि एक बार कर्मचारी की सेवा नियमित हो जाने और



उसे नियमित प्रतिष्ठान में शामिल कर लिए जाने के बाद सेवा एवं सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ तय करते समय उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रेंति के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पिछली तारीख से कानून बनाकर कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति की स्थिति को फिर से आधार नहीं बना सकती और उसे उन पेंशन लाभों से वंचित नहीं कर सकती, जो नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी सेवा को पिछली तारीख से पेंशन की गणना से बाहर रखने को केवल नयी कानूनी परिभाषाएं लागू करके या पेंशन से वंचित करने वाले पुराने आदेशों को वैध ठहराकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। फैसले में कहा गया कि केवल नयी वैधानिक परिभाषाएं लागू करके या पेंशन से वंचित करने वाले पुराने आदेशों को वैध ठहराकर ऐसी सेवा को पिछली तारीख से बाहर नहीं किया जा सकता। यह विवाद तब पैदा हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने प्रेम सिंह मामले में दो सितंबर, २०१६ के अपने फैसले में यह कहा कि कार्य–आधारित प्रतिष्ठान में की गई सेवा को पेंशन के लिए पात्र सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए। उस समय अदालत ने उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, १९६१ के नियम ३(८) के प्रावधानों की सीमित व्याख्या करते हुए निर्देश दिया था कि पात्र कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ दिए जाएं। हालांकि, इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने २०२० में एक अध्यादेश जारी किया और बाद में २०२१ का विधिमान्यकरण अधिनियम बनाया, जिसके जरिए अर्हक सेवा से जुड़े नियमों में पिछली तारीख से बदलाव किया गया। राज्य सरकार ने २०२५ में एक और अध्यादेश जारी किया और इसके बाद उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, २०२५ बनाया। इसमें पेंशन की पात्रता तय करने के लिए 'मूल पद पर नियुक्त कर्मचारीश की अवधारणा भी पेश की गई। कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों ने इन विधायी प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार विधायी भाषा के जरिए उसी सेवा को पेंशन के दायरे से बाहर करने की कोशिश कर रही है, जिसे अदालत २०१६ के बाध्यकारी फैसले में पहले ही खारिज कर चुकी थी। अपने आदेश में पीठ ने निर्देश दिया कि पात्र कर्मचारियों के पेंशन संबंधी दावों पर प्रेम सिंह मामले में दिए गए फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाए। फैसले के दायरे में आने वाले प्रत्येक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़े अन्य लाभों के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें वर्षों के दौरान दी गई अपनी सेवा का पूरा ब्योरा देना होगा। संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक दावे की प्राप्ति के छह महीने के भीतर उसकी जांच कर फैसला करें और पात्र पाए जाने पर संबंधित लाभ प्रदान करें।

लखनऊ जेल में बंद समरीन हत्याकांड के आरोपी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोपय हिरासत में मौतों पर फिर उठे सवाल

लखनऊ। ओमेक्स न्यू हजरतगंज के होटल होटल सेलेस्टियल मैनर के दसवें तल से गिरकर हुई समरीन की मौत के मामले में जेल में बंद हत्यारोपी प्रेमी अवनीश (३०) की संदिग्ध हालात मौत पर परिवारवाले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जेल प्रशासन का दावा है कि अवनीश ने तौलिए से फंदा लगाकर जान दी है। लेकिन परिजन इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। छोटे भाई आशुतोष जायसवाल ने बताया कि १७ नवंबर को वे अवनीश से मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। तब वह सही था। अवनीश ने कहा था कि १५ दिन में मुलाकात किया करिए। अवनीश किसी तरह के तनाव में नहीं था। परिवारीजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों की मानें तो अवनीश का बैरक में ही बंद एक बंदी से विवाद हुआ था। दोनों में मारपीट भी हुई थी। चर्चा यह भी है कि उसी बंदी ने ही अवनीश की हत्या कर दी। हालांकि जेल प्रशासन किसी भी तरीके के विवाद से इंकार कर रहा है। गुरुवार सुबह ६ बजे जेल प्रशासन ने परिवारवालों को सूचना दी। भाई आशीष कुमार के मुताबिक, जेल प्रशासन ने अवनीश की तबीयत खराब होने की बात कही थी। परिवार वाले जेल पहुंचे। वहां बताया गया कि बलरामपुर इलाज के लिए भेजा गया है। परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अवनीश की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम हाउस पर परिजन को बुलाया गया। भाई आशीष का आरोप है कि जेल के शौचालय में अवनीश की हत्या की गई है। भाई ने गोसाईंगंज पुलिस को तहरीर भी दी है। सोशल मीडिया पर अवनीश की हत्या किए जाने का मैसेज गुरुवार को वायरल हुआ । इसमें जेल में बंद तौहीद उर्फ भूरा पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि, इस आरोप की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी का कहना है कि बैरक में ४४ बंदी थे। अगर हत्या होती तो चीख–पुकार जरूर मचती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैरक में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और उनकी निगरानी मुख्यालय से होती है। परिवार ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और घटना से पहले की गतिविधियों की जांच कराने की मांग की है। डीआइजी जेल धनीराम का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। खाकी की जिम्मेदारी सिर्फ आरोपियों को पकड़कर हवालात या जेल में डालना ही



नहीं, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। राजधानी में जेल व थानों के हवालातों में होने वाली मौत पर हर बार सवाल खड़े होते हैं। पर, इसके जिम्मेदारों की जवाबदेही अधूरी है। कभी जेल के शौचालय में बंदी का शव मिलता है तो कभी थाने के ल कअप या पुलिस वाहन में व्यक्ति की जान चली जाती है। हर घटना के बाद जांच, निलंबन और एफआईआर की कार्रवाई होती है, लेकिन हिरासत में बंद लोगों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में खामियां सामने आती रही हैं। अवनीश जायसवाल की जेल में संदिग्ध मौत ने एक बार फिर पुराने घटनाओं को ताजा कर दिया है। पुलिस हिरासत व जेल में निरुद्ध आरोपियों की मौत के मामलों में सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। बंदी की तबीयत बिगड़ने पर समय से उपचार, मानसिक स्थिति पर नजर और नियमित निगरानी की जिम्मेदारी किस स्तर पर निभाई गई? सीसीटीवी कैमरे और ड्यूटी रजिस्टर के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रोकी जा सकीं? हर मामले में जांच के साथ व्यवस्था की खामियों को दूर करने की जरूरत भी सामने आती है। २१ मार्च २००६ को टिकट के बिना यात्रा करने के आरोप में जिला जेल में बंद राजू की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना के बाद जेल में बंदियों की स्वास्थ्य निगरानी पर सवाल उठे थे। एनआरएचएम घोटाले के आरोपित डॉ. योगेंद्र सचान का २२ जून २०११ को जिला जेल के शौचालय में शव मिला था। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया, जबकि सीबीआई ने आत्महत्या की बात कही थी। वर्ष २०२२ में विशेष सीबीआई अदालत ने प्रथम दृष्टया हत्या और साजिश की आशंका जताते हुए सात लोगों को तलब किया था। ११ अक्टूबर २०२४ को विकासनगर के सेक्टर आठ स्थित आंबेडकर पार्क में जुआ खेलने के शक में पुलिस ने अमन गौतम को पकड़ा था। पुलिस वाहन में तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। परिवार ने पिटाई का आरोप लगाया था। चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। २६ अक्टूबर २०२४ को चिनहट थाने के लॉकअप में कारोबारी मोहित पांडेय की मौत हो गई। परिवार ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। लॉकअप के सीसी कैमरे के फुटेज में उनकी तबीयत बिगड़ने के दृश्य सामने आए। थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन घटनाओं ने हिरासत में बंद व्यक्तियों की सुरक्षा, निगरानी और समय पर चिकित्सकीय सहायता की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केवल घटना के बाद कार्रवाई नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें हिरासत में किसी की जान जाने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके।

अटल आवासीय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, कक्षा ६ और ९ की १४८ सीटों के लिए ५ जनवरी तक करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र २०२७–२८ के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित सिठौली कला के अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा छह और नौ में दाखिले के लिए २० नवंबर से आवेदन किए



जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अ नलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भर सकते हैं। इस बार कुल १४८ सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख ५ जनवरी २०२७ तय की गई है। अपर श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र कल्पना श्रीवास्तव के अनुसार इस विद्यालय में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले छह जिलों के पात्र बच्चों को दाखिला मिलेगा, जिनमें लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और हरदोई शामिल हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीत ऐसे निर्माण श्रमिकों के बच्चे आवेदन के पात्र हैं, जिनके माता–पिता की पंजीयन सदस्यता को कम से कम तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ ही कोविड–१९ महामारी के दौरान अपने माता–पिता या अभिभावक को खोने वाले निराश्रित बच्चों को भी प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत पात्र बच्चे भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित पात्रता मानदंडों और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। विद्यालय प्रशासन के अनुसार कक्षा छह में प्रवेश के लिए कुल १४० सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से ७० सीटें बालकों और ७० सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं कक्षा नौ में कुल आठ सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा और ये सभी सीटें बालिकाओं के लिए तय की गई हैं। इस प्रकार दोनों कक्षाओं को मिलाकर कुल १४८ विद्यार्थियों को दाखिला प्रदान किया जाएगा। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित जिले के श्रम विभाग कार्यालय, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट **upbocw- in** से भी डाउनलोड कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ तीन अतिरिक्त फोटो संलग्न कर संबंधित जिले के श्रम विभाग कार्यालय में शाम पांच बजे तक जमा करना होगा, जिसके बाद निर्धारित तिथि को सुबह ११ बजे से दोपहर एक बजे तक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।

दुधवा में जल्द बसाऐ जायेंगें जंगली जलभैंसे, बनेगा अलग बाड़ा

पलिया कलां लखीमपुर खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व में चार दशक पहले विलुप्त हो चुके जंगली जल भैंसों (वाइल्ड वाटर बफैलो) को दोबारा दुधवा टाइगर रिजर्व में बसाने की कवायद तेज हो गई है। जंगली जल भैंसों के लिए उपयुक्त स्थान के चयन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से अध्ययन कराया जा रहा है, घास के मैदानों की गुणवत्ता, जल स्रोतों की उपलब्धता और कम मानवीय हस्तक्षेप के कारण इस योजना के लिए दुधवा को उपयुक्त माना गया है। जल्द ही कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद संभवतः वित्तीय वर्ष २०२७–२८ के शुभारंभ तक असम के जंगलों से जलभैंसों का समूह दुधवा लाकर उन्हें यहां बसाने की व्यवस्था पूरी कर ली जायेगी। वन्यजीवों की सुरक्षा को देखते हुए पार्क प्रशासन ने इनकी रिहाइश की योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इन्हें गैंडों के बाड़े (राइनो एरिया) में न रखकर इनके लिए एक अलग और पूरी तरह सुरक्षित बाड़ा तैयार किया जाएगा। जंगली जल भैंसों के लिए उपयुक्त स्थान के चयन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से अध्ययन कराया जा रहा है। घास के मैदानों की गुणवत्ता, जल स्रोतों की उपलब्धता और कम मानवीय हस्तक्षेप के कारण इस योजना के लिए दुधवा को चुना गया है। दरअसल, पहले प्रशासन इन्हें राइनो एरिया में रखने की तैयारी कर रहा था, लेकिन असम से आए वन्यजीव विशेषज्ञों ने सुरक्षा कारणों से इस पर आपत्ति जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि राइनो एरिया में बाघों की लगातार आवाजाही रहती है। गैंडे तो बाघ के हमले का सामना कर सकते हैं, लेकिन जल भैंसे बाघों के सामने अधिक संवेदनशील होते हैं। इसी वजह से अब ऐसा विशेष बाड़ा और फेंसिंग तैयार की जाएगी, जिसमें बाघ या अन्य हिंसक वन्यजीव दाखिल न हो सकें। दुधवा टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. एच. राजामोहन के अनुसार, विशेषज्ञों की सलाह पर वाटर बफैलो के लिए अलग से सुरक्षित बाड़ा बनाया जाएगा और असम की विशेषज्ञ टीम द्वारा इसके भौतिक सत्यापन के बाद ही पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं, डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने बताया कि जंगली जल भैंस एक संकटग्रस्त प्रजाति है और स्थान चिह्नित होते ही जमीनी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। इस बाबत कागज की पूरी कार्रवाई चल रही है और संभवत सन् २०२७ के मार्च के महीने में इन जल भैंसों को दुधवा लाया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष १९८४ में दुधवा में शुरू हुई गैंडा पुनर्वास योजना बेहद सफल रही है। असम से लाए गए पांच गैंडों और १९८५ में नेपाल से लाई गईं चार मादा गैंडों के बाद अब यहां इनकी संख्या बढ़कर लगभग ५० हो गई है।

मां के निधन की खबर के बावजूद विद्यार्थियों के बीच पहुंचे योगी, मातृशोक में भी निभाया कर्तव्य

लखनऊ/गोरखपुर। सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत पीड़ा और संवैधानिक दायित्वों के बीच संतुलन साधना हर किसी के वश की बात नहीं होती, लेकिन गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाबा गोरखनाथ की धरती से कर्तव्यनिष्ठा और राजधर्म की एक ऐसी हृदयस्पर्शी मिसाल पेश की, जिसने हर संवेदनशील मन को भावुक कर दिया है। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में विद्यार्थियों के लिए आयोजित टैबलेट वितरण समारोह के दौरान जब मुख्यमंत्री को मां के निधन की हृदयविदारक सूचना मिली, तब भी उन्होंने अपनी निजी पीड़ा और अंतर्मन में उमड़े असहनीय शोक को युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के मार्ग में नहीं आने दिया। इस अपूरणीय क्षति की सूचना के बाद भी उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कार्यक्रम संपन्न कराया। गोरखपुर मंडल के ५० हजार विद्यार्थियों के लिए टैबलेट वितरण के समारोह का माहौल बेहद उत्सवी और उत्साहपूर्ण था। मंच पर २३ विद्यार्थियों को अपने हाथों से टैबलेट देने के बाद सीएम योगी अपने संबोधन से हजारों विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहे थे, उनका करियर कैसे संवरेगा, इसके लिए गुरुमंत्र दे रहे थे जैसे ही उनका प्रेरक संबोधन समाप्त हुआ तो वह विद्यार्थियों के बीच जाकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मंच से उतरने को बढ़े। मुख्यमंत्री के पोडियम से हटते ही उन्हें माता सावित्री देवी जी के निधन की अत्यंत दुखद सूचना दी गई। मां के गोलोकवासी होने की जानकारी मिलते ही योगी की आंखें भर आईं। दुःख और शोक से मिश्रित अंतर्मन



की भावनाएं उमड़ने को हुईं, लेकिन मुख्यमंत्री ने सामने हजारों माताओं के बच्चों को बैठे देखा जो उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों को लेकर उत्साह से लबरेज थे। उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री भाषण खत्म करने के बाद उनके बीच जरूर आएंगे। मुख्यमंत्री ने क्षण भर में ही विद्यार्थियों की उम्मीदों को भांप लिया। अथाह निजी पीड़ा और शोक को परे रखकर वह संयत होकर विद्यार्थियों के बीच पहुंचे। उनके साथ सेल्फी लेकर उनसे अनकहा वादा निभाया, उन्हें प्रोत्साहित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। विद्यार्थियों को उस समय इस बात का आभास तक नहीं हो सका कि उनके साथ खड़े प्रदेश के मुखिया इस समय कितने बड़े व्यक्तिगत आघात से गुजर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल छात्र–छात्राओं और शिक्षकों को जब बाद में इस घटना की जानकारी हुई, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। मां का निधन, किसी भी पुत्र के लिए जीवन का सबसे दुखद व कठिन क्षण होता है, लेकिन एक संन्यासी और प्रदेश के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस संयम और धैर्य का परिचय दिया, वह अनिवर्चनीय था। लोगों ने इसे जनसेवा ही सर्वोच्च प्राथमिकताऔर श्राष्ट्र प्रथम संकल्प का जीवंत उदाहरण बताया। मातृशोक की गहरी पीड़ा को भीतर समेटे हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरह युवाओं के कल्याण, उनके भविष्य और प्रदेश सेवा के प्रति अपना समर्पण दिखाया, वह सार्वजनिक जीवन में शुचिता और कर्तव्यपरायणता के मानक के रूप में याद रखा जाएगा।

हनुमान अंश' के लिए विशाल चतुर्वेदी को मिला इंडियन ऑफ द ईयर 2026 सम्मान

मुम्बई। फिल्म 'हनुमान अंश' के लेखक, निर्देशक और निर्माता विशाल चतुर्वेदी को फिल्म के निर्माण में उनकी रचनात्मक सोच, मेहनत और योगदान के लिए इंडियन ऑफ द ईयर २०२६ सम्मान से नवाजा गया है। विशाल चतुर्वेदी ने इस उपलब्धि को अपनी पूरी टीम और फिल्म से जुड़े सहयोगियों को समर्पित करते हुए कहा कि उनके विश्वास और अथक प्रयासों के बिना इस फिल्म को साकार करना संभव नहीं था। सम्मान समारोह में मंच पर पहुंचते ही विशाल चतुर्वेदी ने 'सीता राम' कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि हमारे देश में माताओं और बहनों को पहले स्थान दिया जाता है, इसलिए उनके विचार से यह संबोधन अधिक उपयुक्त है। उन्होंने 'हनुमान अंश' के निर्माण के अनुभव साझा करते हुए कहा कि फिल्म को बनाने का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि, निर्माताओं के विश्वास और पूरी टीम की मेहनत ने इस मुश्किल यात्रा को संभव बनाया। विशाल ने अपने संबोधन में सबसे पहले फिल्म की निर्माताओं रागिनी सोना और नम्रता सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रागिनी

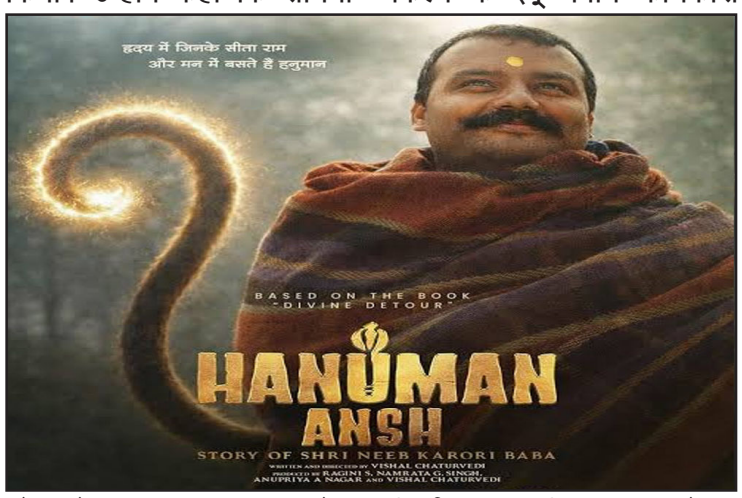

सोना ने उनकी रचनात्मक सोच पर भरोसा किया और फिल्म के निर्माण के दौरान उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी। एक फिल्मकार के लिए निर्माता का विश्वास बेहद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि जब निर्माता या टीम के सदस्य फिल्मकार के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, तो उसकी रचनात्मकता प्रभावित होती है, लेकिन उन्हें इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। इस अवसर पर विशाल ने फिल्म के २५ वर्षीय कार्यकारी निर्माता पीयूष सिंह ठाकुर को भी मंच पर आमंत्रित किया और फिल्म के पहले दिन से उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीयूष के समर्पण और मेहनत के बिना 'हनुमान अंश' का निर्माण संभव नहीं हो पाता। उन्होंने फिल्म के भक्ति गीत 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' को अपनी आवाज देने वाले गायक एवं संगीतकार सुनील लोधी का भी विशेष रूप से आभार जताया। यह गीत फिल्म के शुरुआती लोकप्रिय गीतों में शामिल है और दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका है। विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म में नीम करौली बाबा महाराज की भूमिका निभाने वाले शोभिनव सत्य को भी मंच पर आमंत्रित किया। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम और उन सभी सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने अपने परिश्रम, समर्पण और विश्वास से इस परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मान प्राप्त करने के अवसर को विशाल चतुर्वेदी ने केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि 'हनुमान अंश' से जुड़े सभी सहयोगियों की सामूहिक सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। इंडियन ऑफ द ईयर २०२६ का सम्मान उनके फिल्मी सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

'ये प्रेम मोल लिया' का ट्रेलर रिलीज

मुम्बई। बॉलीवुड फिल्मकार सूरज आर. बड़जात्या की आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आयुष्मान खुराना और शरवरी की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म में प्यार, शादी, परिवार और बदलते सामाजिक रिश्तों की एक दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी। ट्रेलर में पारिवारिक भावनाओं के साथ आधुनिक सोच और रिश्तों के नए नजरिये की झलक दिखाई गई है। फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़े के इर्द–गिर्द घूमती है, जिनका प्यार शादी तक पहुंचता है, लेकिन उनकी शादी पारंपरिक शादियों से बिल्कुल अलग है। इसमें शादी के बाद दुल्हन के बजाय दूल्हा अपनी पत्नी के घर रहने आता है। फिल्म के जरिए विवाह और पारिवारिक



परंपराओं से जुड़े स्थापित विचारों को नए नजरिये से पेश किया गया है। कहानी में महिला किरदार अपने जीवन और वैवाहिक रिश्ते से जुड़े फैसले खुद लेती है। फिल्म यह संदेश देने की कोशिश करती है कि शादी के बाद किसी महिला को अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोनों परिवारों के साथ सामंजस्य बनाकर भी खुशहाल वैवाहिक जीवन जिया जा सकता है। ट्रेलर में आयुष्मान खुराना और शरवरी की जोड़ी के बीच रोमांस और शानदार तालमेल देखने को मिलता है। आयुष्मान का संवाद अगर इतना भी नहीं किया तो क्या प्यार किया?" प्यार के प्रति फिल्म के नजरिये को बयां करता है। सूरज बड़जात्या ने इस बार अपनी पारिवारिक फिल्मों की परंपरा को बरकरार रखते हुए बदलते समय और नई पीढ़ी की सोच को कहानी का हिस्सा बनाया है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566
सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक